ISSN 2319

भारत में कैशलैस भुगतान व्यवस्था

डॉ. एम. एम. चौकसे
प्राध्यापक वाणिज्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

वर्तमान समय में देश का लगभग 95 प्रतिशत लेनदेन नकद आधारित है, जिससे एक बहुत बड़ी अनौपचा अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, इसकी वजह से सरकार को विभिन्न टैक्स लगाने तथा उनकी वसूली में कठि होती है नकद संचालन में भरतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों का सलाना खर्च 21000 करोड़ रूपये आता वर्ष 2016 में भारत में नगदी संचालन कुल जी.डी.पी. का 12.42 प्रतिशत था जबकि चीन में 9.47 प्रतिशत व ब्राजील में 4 प्रतिशत था।

मुख्य शब्द - नगदी , भुगतान, अर्थव्यवस्था।

बैंकों का सालाना खर्च कम करने तथा करों की समुचित वसूली हो सके इस कारण सरकार ने 2016 देश में नोट बंदी की थी कैशलैस अर्थ व्यवस्था न होने के कारण नकद व्यवस्था को चलाने में कुल जीडीपी 0.25 प्रतिशत हिस्सा खर्च होती है।

जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह ना के बराबर हो जाये तथा सभी लेनदेन डेबिट एवं क्रेडिट का तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक फंड्स ट्रांसफर और रीयल टाइम ग्रास सेंटलमेंट जैसे इलेक्ट्रानिक चैन एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे तो यह स्थिति कैशलेस भुगतान के रूप में परिभाषि की जाती है। देश में डिजीटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है भारत में डिजिटल भुगता के मूल्य को तालिका क्रमांक 1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1

वर्ष	मूल्य यू.एस मिलियन (डालर में)
2017	83115
2018	105121
2019	128417
2020	117741
2021	160660 (अनुमानित)
2022	195134 (अनुमानित)
2023	223625 (अनुमानित)
2024	224257 (अनुमानित)

स्त्रोत स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2021

वर्ष 2014 से 2019 के बीच में डिजीटल भुगतान से कुल सकल राष्ट्रीय आय के उसके अंश को प्रतिशत को तालिका क्रमांक 2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 2

वर्ष	प्रतिशत में
2014	542
2015	561
2016	579
2017	644
2018	726
2019	769

स्त्रोत स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2021

कैशलेस भुगतान के तरीके-भारत में कैसलैस भुगतान के जो तरीके अपनाये जा रहे है वह निम्न है-

1. बैंक कार्ड्स।
2. यू. एस. एस. डी.।
3. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली।
4. यू.पी.आई.।
5. मोबाइल वालेट।
6. बैंक प्री.पेड कार्ड्स।
7. प्वाइंट ऑफ सेल्स (POS)।
8. इंटरनेट बैंकिंग।
9. मोबाइल बैंकिंग ।
10. भीम एप।

कैशलैस अर्थव्यवस्था के लाभ

1. लेन देन आसान तथा अधिक सुविधाजनक -

यह भुगतान प्रक्रिया को गति देता है, न ही लम्बी जानकारी भरने की आवश्यकता होती है और नहीं लम्बी कतार में खड़े रहने, न ही अपने पास अधिक नकदी रखने की बैंकिग सेवाये ग्राहकों के लिये 24/7 के आधार पर साल के सभी दिनों में उपलब्ध रहती है।

2. किफायती और कम लेनदेन शुल्क -

कई भुगतान ऐप और मोबाईल ऐप ऐसे भी है जो दी गई सेवा के बदले में ग्राहक से किसी भी प्र... का शुल्क नहीं लेते विभिन्न डिजीटल भुगतान प्रणाली लागत में कमी आ रही है।

3. छूट और कैश बैक -

डिजीटल भुगतान ऐप और मोबाइल वालेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों को कई पुरस्कार और छूट प्र... की जाती है। कई डिजिटल पेमेंट बैंकों द्वारा आकर्षक कैशबैक भी दिया जाता है।

4. लेनदेन का डिजीटल रिकार्ड -

डिजीटल होने के कारण सभी लेनदेनों का रिकार्ड बनाये रखा जा सकता है ग्राहक प्रत्येक लेन देन को ... सकते है चाहे लेनदेन कितना भी बड़ा हो अथवा छोटा।

5. काले धन को नियंत्रण रखने में मदद -

डिजीटल लेनदेन से सरकार को चीजों पर नजर रखने में मदद मिलती है। यह आने वाले समय में का... धन और जाली नोंटों के प्रचलन को खत्म करने में मददगार साबित होगी।

6. बिलों के भुगतान के एक ही स्थान पर समाधान - कई डिजीटल बालेट और पेमेन्ट ऐप यूटीलिटी बिलों का प्र... सुविधाजनक प्लेट फार्म बन गए है। चाहे बिजली बिल हो, सम्पत्ति कर हो अथवा बीमा पालिसी की किश्त इन स... उपयोगी बिलों का भुगतान बिना किसी परेशानी के एक ही ऐप के जरिये किया जा सकता है।

डिजीटल पेमेंट पर प्राप्त छूटें -

1. सर्विस टैक्स - 2000 रूपये से कम के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर 10% सर्विस टैक्स की बचत।
2. ईधन भरवाने पर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड्स, ई वालेट या मोबाइल वालेट की मदद से पेंमेट पर 0.75% की छूट।
3. रेल टिकिट्स - मंथली और सीजन टिकिट पर 1 जनवरी से 0.5% की छूट ऑनलाइन रेल टिकिट पर 10 लाख रूपये का बगैर शुल्क का बीमा।
4. रेल केंटिरिंग - रेल केंटरिंग ठहरनें रिटायरिंग रूम आदि के लिये डिजीटल पेंमेट करने पर 5% छूट।
5. इंश्योरेंस - पोर्टल के जरिये साधारण बीमा खरीदने या प्रीमियम के पेंमेंट पर 18% डिस्काउंट।
6. एल.आई सी. की पालिसी आनलाइन लेने पर 8% डिस्काउंट।
7. पी.ओ.एस. - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पी.ओ.एस. टर्मिनल के लिये सिर्फ 100 रूपये तक रेट चार्ज कर सकते है।
8. रूपे - किसान कार्ड वाले लोगों को रूपे किसान कार्ड मिलेगें।

कैशलैस भुगतान व्यवस्था के नुकसान

1. हमारे देश में 70% आवादी गाँवों में निवास करती है जहां डिजीटल पेंमेंट करना हर किसी को नहीं आता है आज भी देश में नकद रहित भुगतान केवल शहरी तथा अर्द्ध शहरी केन्द्रों तक सीमित है। ग्रामीण भारत

में आज भी बढ़ी आबादी कम शिक्षित तथा अनपढ़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 22% घरों में अभी भी बिजली नहीं है।

2. अधिकतम जनसंख्या के कम पढ़ी लिखी होने के कारण अशिक्षित व्यक्ति दूसरे लोंगों की सहायता लेती है चालक व धूर्त लोग आसानी से इन्हें अपना शिकार बनाते है तथा यह लोग धोखाधड़ी का शिकार होते है।

3. ऑन लाइन पेमेंट पर लोंगों को आज भी शुल्क देना पड़ता है जबकि नकद भुगतान में इस शुल्क से बचा जा सकता है।

4. देश में आज भी इंटरनेट तथा मोबाइल सुविधाओं की कमी है देश में सारी आबादी के पास आज भी स्मार्ट फोन है जबकि डिजीटल पेमेंट के लिये यह आवश्यक है।

5. आइडेंटिटी चोरी का जोखिम - नेट बैंकिंग तथा मोबाइल से पेमेन्ट करने पर व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का डर सदैव बना रहता है, व्यकितगत जानकारी का दुरूपयोग होने के अनेक उदाहरण सामने आते है हैकर पासवार्ड की चोरी से बैंक से पैसा निकाल लेते है।

वर्तमान स्थिति -

कैशलेस इकोनिमी के प्रति सरकार का अभियान फलफूल रहा है वर्ष वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच में भारत में डिजीटल भुगतान के रूप में 55.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है 2016-17 में मात्र 593.61 करोड़ तथा मूल्य 1120.99 लाख था जो 2018 में 2343.40 करोड़ तथा मूल्य 1638.52 लाख करोड़ रूपये हो गया। अनुमान किया गया है 2025 तक डिजीटल अर्थव्यवस्था में 6 से 6.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। भारत सरकार में वर्ष में 2021 तक डिजीटल लेनदेन 135.2 अरब डालर होने का अनुमान है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 के बजट में डिजीटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया।

उम्मीद की जानी चाहिए कि डिजिटल अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य समस्यायें, ग्रामीण क्षेत्र के लोंगों में जागरूकता लानी होगी, केशलैश लेनदेनों से पारदर्शिता आयेगी, कैश चोरी पर अंकुश लगेगा, कालेधन के प्रयोग पर रोक हो सकेगी तथा जाली मुद्रा प्रचलन में नहीं रहेगी रोजगार के अवसर बढ़ेगे आर्थिक क्रियाकलापों में पारदर्शिता आयेगी और देश विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकेगा।

संदर्भ -

1. रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 2017-2020
2. स्टेटिस्टा रिपोर्ट 2020-21
3. विकीपीडिया रिपोर्ट।
4. www.bankbazar.com
5. einhindi.com/blog/digital payment system